



केंद्रीय बजट 2023-24



# केंद्रीय बजट 2023-24

अमृत काल का पहला बजट

भाग - A

## बजट और अमृत काल

- विज्ञान- सशक्त, समावेशी अर्थव्यवस्था ( प्रौद्योगिकी-चालित, ज्ञान-आधारित एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र के साथ )

## बजट के सप्तर्षि

### → समावेशी विकास:

#### → कृषि:

- ◆ कृषि के लिये डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना
- ◆ कृषि-स्टार्टअप के लिये कोष की स्थापना
- ◆ बागवानी फसलों के लिये आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम
- ◆ भारत को कदन्न अर्थात् 'श्री अन्न' ( पोषक अनाज/कदन्न ) हेतु एक वैश्विक केंद्र बनाना

#### → शिक्षा एवं कौशल:

- ◆ शिक्षण प्रशिक्षण का सुधार
- ◆ राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना
- ◆ पंचायत/वाड स्तर पर पुस्तकालयों की भौतिक उपस्थिति

#### → स्वास्थ्य:

- ◆ 157 नए चिकित्सा महाविद्यालय
- ◆ सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन हेतु मिशन

### → अंतिम छोर तक पहुँचना:

- आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता के आधार पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया
- PVTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा ( निधि-15,000 करोड़ रुपए ) प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिये भारत श्री की स्थापना की जाएगी
- प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिये भारत श्री की स्थापना की जाएगी

### → अवसंरचना और निवेश:

- पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए ( अब GDP का 3.3% )
- राज्य सरकारों को 50 वर्ष के व्याज मुक्त ऋण को एक और वर्ष के लिये जारी रखने का फैसला
- टियर 2/3 शहरों के लिये शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) की स्थापना की जाएगी

### → क्षमता उभारना:

- कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन ( 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया गया )
- विश्वास पर आधारित शासन को आगे बढ़ाने के लिये जन विश्वास विधेयक पेश किया गया
- ई-न्यायालय चरण III

### → हरित विकास:

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
- गोबरधन (GOBARdhan) योजना- 500 नए 'अपशिष्ट से आमदनी' संयंत्र
- पीएम प्रणाम- वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग करने के लिये राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करना
- मिष्ठी (MISHTI) initiative for mangrove plantation

### → युवा शक्ति:

- पीएम कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी
- राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

### → वित्तीय क्षेत्र:

- MSME के लिये क्रेडिट गारंटी योजना को नया प्रारूप दिया गया
  - ◆ अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए के संपाड़िक मुक्त गारंटीकृत ऋण
  - ◆ क्रेडिट की लागत लगभग 1% कम हो जाएगी
- महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र- एकमुश्त नई लघु बचत योजना - 2 वर्ष के लिये ( मार्च 2025 )

## राजस्व प्रबंधन

### → राजस्व घाटा:

- 6.4% ( वित्तीय वर्ष 22-23 )
- जीडीपी का- 5.9% अनुमानित ( वित्तीय वर्ष 23-24 )
- लक्ष्य - <4.5% ( वित्तीय वर्ष 25-26 तक )

- राज्यों को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का 3.5% घाटा रखने की अनुमति

[और पढ़ें....](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/union-budget-2023-24-2>

